

चौथी योजना के दौरान, देश में इन वन-रोपण योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 833.90 हजार हेक्टर क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है।

1966-67 से 1968-69 के तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में इन योजनाओं के अन्तर्गत, 68.35 हजार हेक्टर क्षेत्र में पौधे लगाये गये। चौथी योजना के दौरान, राज्य में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 148 हजार हेक्टर का क्षेत्र राज्य द्वारा लाया जायेगा।

जहाँ तक भू-अरण का सम्बन्ध है, वनों-मूलन और तत्पश्चात के समय, जब क्षेत्र अन्य कार्यों के लिये प्रयोग किये जाते हैं, सम्बन्धित राज्य वन विभाग साधारणतः उचित कदम उठाते हैं।

(ग) वन पौधे बनाने के लिये, वन अस्थायी और मीसमी रोजगार के समाधानों की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करते हैं। पौधरोपण योजनाओं में लगे कार्मिकों की संख्या के सम्बन्ध में राज्य वन विभागों ने कोई विशिष्ट अध्ययन अभी तक नहीं किये हैं। फिर भी, राज्य वन विभागों के मार्गदर्शन के लिये मन्त्रालय ने श्रम समाधानों के बारे में अनुमान लगाये हैं। इन अनुमानों से पता चलता है कि पौधरोपण कार्यक्रमों में श्रम संसाधन काफी अधिक है। इसके अनुसार इन कार्यक्रमों के लिये 146.6 लाख व्यक्तियों के श्रम का एक दिन प्रयोग किया, जो 1966-67 से 1968-69 की अवधि में राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा 442.60 हजार हेक्टर में पौधरोपण करने के लिये 48,900 कार्मिकों को पूर्णकालिक राजगार प्रदान करने के बराबर है।

बेरोजगारी भत्ता

512 श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट . क्या श्रम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हा, तो यह भत्ता किम तारीख से दिया जायेगा तथा इस प्रयोजनार्थ क्या माप-दण्ड अपनाये जायेगे ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) जी नहीं।

(ख) गबाल पैदा नहीं होता।

चीड़ उद्योग के उत्पादों का अध्ययन करने हेतु सम्मेलन

513 श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट . क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चीड़ उद्योग में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अप्रैल, 1971 में चीड़ उद्योग के उत्पादों का अध्ययन करने हेतु नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) यदि हा, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या चीड़ उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को भी उक्त सम्मेलन में आमन्त्रित किया गया था , और

(घ) उन्होंने इस सम्बन्ध में सरकार को क्या सुझाव दिये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) बिरोजा तथा तारपीन के उत्पादकों तथा परिसंस्करणकर्ताओं द्वारा, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 13 तथा 14 अक्टूबर, 1971 को एक विचार गोष्ठी प्रत्यायोजित की गई थी। भारतीय रसायन निर्माता संघ, भारतीय पेपर मिल संघ, भारतीय पेंट संघ आदि जैसे विभिन्न अखिल भारतीय संगठन इसके सह-प्रायोजक थे। विचार गोष्ठी का विषय 'भारत के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में पाइन रेजिन की भूमिका' था।

(ख) प्रायोजकों ने विचार गोष्ठी से सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की